



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 1982/ज्येष्ठ 19, 1904

No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 1982/JYAJSTHA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन से बन न
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राज्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून, 1982

संकल्प

फा०सं० 21/7/81-विक्री-कर—दिनांक 1 मार्च, 1982 के संकल्प फा० संख्या 21/7/81-
बि०क० के पैरा 3 में प्राथमिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि वनस्पति,
घोषध-द्रव्यों और दवाइयों, सोमेट, कागज और गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादों को घोषित भाव
की सूची में शामिल करने तथा उन पर लगने वाले विक्री-कर के स्थान पर प्रतिरिक्त उत्पादन
शुल्क लगाने संबंधी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों और उन तरीकों का अध्ययन करने के लिए जिनसे
राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा की जा सकती है नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्टें
30 जून, 1982 को बजाय 30 सितम्बर, 1982 तक प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों/कार्वायों को भेज दी जाए।

इस भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

उपसिद्ध बल, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th June, 1982

RESOLUTION

F. No. 21/7/81-ST.—In partial modification of para 3 of the Resolution F. No. 21/7/81-ST dated the 1st March, 1982, the Government have decided that the Expert Committee appointed to study the financial implications of the proposal for inclusion in the list of declared goods and for levy of additional excise duty in lieu of sales tax on vanaspati, drugs and medicines, cement, paper and paper board and petroleum products and the manner in which the financial interests of the States can be safeguarded, will submit its report by 30th September, 1982 instead of the 30th June, 1982.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette for general information.

J. DATTA, Addl. Secy.